International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 9 Issue 5, May 2019,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

स्कूल ड्रॉपआउट की समस्या एवं उसके रोकथाम के लिए किये गए प्रयासों का अध्यन

विनीता सिंह
शोधकर्ती, राजा श्री कृष्ण दत्त पीजी. कॉलेज जौनपुर
डॉ. नीता सिंह
असिस्टेंट प्रोफेसर, शिक्षाशास्त्र विभाग, राजा श्री कृष्ण दत्त पीजी. कॉलेज जौनपुर

स्कूल छोड़ने की रोकथाम अंतरराष्ट्रीय शिक्षा की चिंता का तुलनात्मक रूप से एक नया ध्यान केन्द्र है। पिछले दो दशकों में स्कूलों तक अधिक से अधिक बच्चों के पहुंचने पर ध्यान केनद्रित है, पर हाल ही में, शिक्षा की गुणवत्ता पर, जिसमें शैक्षिक उपलब्धि को बेहतर करने के लिए निर्देश, सामग्रियाँ और संसाधन शामिल है पर ध्यान देना शुरू हुआ। हाल ही में यह ध्यान केन्द्र बदलकर स्कूल छोड़ने और एक कक्षा के दोहराव को रोकने के प्रयासों को शामिल करना भी हो गया है। जहाँ विकासशील देशों में स्कूल छोड़ने के बारे में शेध ने स्कूल छोड़ने वाले छात्रो का वर्णन करने में काम किया है, वहीं स्कूल छोड़ कर जाने के बचाव के सफल तरीकों के बारे में बहुत कम जानकारी है।

1. प्रस्तावना

शिक्षा के क्षेत्र में भारत में ऐसी कई उपलब्धियां जो हमें प्रसन्नता से भर देंगी। भारत में कम से कम 7 करोड़ बच्चे प्री–प्राइमरी स्कूलों में जाते हैं। देश में लगभग सभी बच्चों का प्राइमरी स्कूलों में नामांकन है, और सात राज्यों में शिक्षा के बेहतर परिणाम आए हैं।अपर प्राइमरी (लोअर सेकण्डरी) कक्षाओं की सहभागिता निरंतर बढ़ रही है।

हालांकि, अभी बहुत कुछ किया जाना बाकि है क्योंकि स्कूल जाने वालेअधिकांश बच्चे उम्र के अनुसार सही कक्षा मेंपढ़ाई नहीं कर रहे हैं। छात्रों के लिए खराब गुणवत्ता की शिक्षण सामग्रीतथा अध्यापक केन्द्रित सीखने और सिखाने की प्रथाएं बच्चों को शिक्षा व्यवस्था से बाहर कर रही हैं।

भारत में 6–13 वर्ष आयु वर्ग के लगभग 60 लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते और इनमें से अधिकांश अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और धार्मिक अल्पसंख्यक समूहों के वंचित समुदायों से हैं।

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 9 Issue 5, May 2019,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

लगभग 36 प्रतिशत लड़कियां और लड़के प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने से पहले ही स्कूल छोड़ देते हैं। यदि इसमें प्रारंभिक शिक्षाऔर हाई स्कूल के बाद स्कूल छोड़ने वालों की संख्या जोड़े तोयह संख्या और भी विवादपूर्ण और चिंताजनक हो जाती है। येबच्चे आमतौर पर अति वंचितहोते हैं। यूनिसेफ भारत के छह राज्यों में स्कूल न जाने वाली लड़कियों की संख्या 14.4 लाख तक कम करने के लिए अपने सहयोगियोंके साथ काम कर रहा है।

स्कूल न जाने वाले अधिकतर (75 प्रतिशत) बच्चे छह राज्योंः बिहार, मध्यप्रदेश, ओडिसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से हैं।

शिक्षा के क्षेत्र में यूनिसेफ कीभारत सरकार के साथ रणनीतिक भागीदारी है जिसका उद्देश्यहै शिक्षा के सिद्धांतों एवं मूल्यों को अनुकूल बनाकर भारतीय समाज के व्यापक समुदायों के लिए शिक्षा को उपयुक्त बनाना।

यह मानते हुए कि कक्षा 1 में पढ़ाई शुरू करने वाले बच्चों में 37 प्रतिशत प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं कर पाते और जो प्रारंभिक शिक्षा पूरी करते हैं उनकी पढ़ाई का स्तर इतना अपर्याप्त होता है कि अगले स्तर की शिक्षा के साथ उनका सामंजस्य नहीं बैठ पाता, हमारा कार्य बचपन से लेकर प्रारंभिक शिक्षा तक सभी बच्चों के लिए अच्छी गुणवत्ता, कक्षा–उपयुक्त शिक्षा देने पर केन्द्रित है। ऐसा सभी स्तरों पर सरकारी सिस्टम मजबूत करके और शैक्षणिक कार्यक्रम के समन्वय, कार्यान्वयन और निगरानी को प्रभावी बनाकर किया जाता है।

यूनिसेफ की शिक्षा प्रणाली जो सभी बच्चों के स्कूल जाने और पढ़ाई सुनिश्चित करती है,में शामिल हैंः

1) शुरुआती शिक्षा मजबूत करने के लिए साक्षरता और संख्यात्मक कौशल का आधार विकसित करना

2) सभी स्तरों पर, विशेषकर लड़कियों और वंचित समूहों के लिए परिवर्तन में सहायता देना

3) प्रारंभिक स्तर पर अंतरणीय कौशलों के साथ पढ़ाई के लिए सुरक्षित माहौल बनाना

भारत के 25 करोड़ किशोरों को अपने विकास के लिए अनिवार्य आर्थिक अवसरों तक पहुँचानेके लिए सेकण्डरी शिक्षा में अपेक्षित बुनियादी और अंतरणीय कौशल प्रोत्साहित करना बेहद महत्वपूर्ण है।

यूनिसेफ 3 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के जीवन कौशल विकास (शिक्षा, स्वयं–सशक्तिकरण, सामाजिक और रोजगार संबंधी कौशल) को सशक्त बनाने के लिए भी सरकार की मदद करता है। ये सॉफ्ट स्किल बच्चों को भारत के तेजी से बढ़ते हुए वातावरण में कामयाब होने के लिए बहुत जरूरी है। इस दृष्टिकोण के मुताबिक सरकार को विशिष्ट फ्रेमवर्क विकसित करने में मदद करना और लगातारव्यावसायिकविकास में जीवन कौशल समाहित करने के लिए योजनाओं का कार्यान्वयन, शिक्षण तथाअध्ययन और स्कूलिंग का

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 9 Issue 5, May 2019,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

आयोजन करना शामिल है। इसके अलावा,स्कूलों में विकास तथा नेतृत्व क्षमता को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों में चिल्ड्रन्स कैबिनेट द्वारा आयोजित खेल–कूद कार्यक्रम भी कारगर साबित हुए हैं।

हमारी मदद से शुरुआती बचपन शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी और समानता एवं समावेशिता भी आएगी जिससे सभी बच्चों की विकासात्मक तैयारी सुनिश्चित करेगी। हम समय पर नामांकन, नियमित उपस्थिति और प्रारंभिक और सेकण्डरी आयु के बच्चों के लिए लचीली शिक्षा प्रणाली से स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या 30 लाख तक कम करना चाहते हैं। इसके अलावा, हम बुनियादी और अंतरणीय कौशल विकास सुनिश्चित करते हुए पढ़ाई के स्तर में 15 प्रतिशत तक सुधार करना चाहते हैं।

2. छात्रो को स्कूल छोड़कर जाने से कैसे रोक सकते हैं

विद्यालय छोड़ने की समस्या को संबोधित करने के लिए सफलता वाले अलग–अलग कई प्रयास किए गए हैं। विद्यालय छोड़ने के कारण के बारे में साहित्य की 2011 एसडीपीपी द्वारा की समीक्षा इन कारणो को पांच वर्गों में बांटती है, जिनमें से प्रत्येक अलग किस्म के मुद्दे से सम्बन्धित है:

- शैक्षिक कार्यक्रम जो सीधक छात्र की उपलब्धित से सम्बन्धित है जैसे छात्र की आवश्यकताओ को बेहतर ढंग से कक्षा के बाद शैक्षणिक टयूशन उपलब्ध कराना, या विशेष कक्षाएं आयोजित करना (जैसे कम्पयूटर की सहायता से सीखना, समस्या समाधान कौशल)।

- वितीय कार्यक्रम घर पर सहायता करने या काम से धन कमाने में सहायता करने की अपेक्षा विद्यालय का बोझ कम करने के लिए या छात्रो के विद्यालय में बने रहने की कीमत के अवसर के लिए वित्तीय कार्यक्रम की व्यवस्था।

- स्वास्थ्य कार्यक्रम इस अनुमान पर आधारित होते हैं, कि बच्चे अनुकूल ढंग से सीख नहीं सकते हैं, जब तक कि वे स्वास्थ्य समस्याओ का सामना कर रहे हैं, जो उनकी ध्यान केन्द्रित करने की क्षमता को सीमित करता है या अनुपस्थिति का कारण है, इसलिए वे बच्चों के लिए टीकाकरण, कीड़े मारने की दवाई या खाना देने की व्यवस्था कर सकते हैं।

- व्यक्तिगत/सामाजिक कार्यक्रम जो सीखने के रास्ते में आ रहे रवैयो, मूल्यो या निजी मूल्यो से सम्बन्धित है जैसे गहन केस प्रबन्धन, परामर्श साथी चर्चा समूह, परिवारिक संघर्श, प्रशिक्षण या स्कूल कार्यकर्ताओ द्वारा निगरानी आदि। निजी/सामाजिक हस्ताक्षेप गहन मामला प्रबंधन, सलाह, साथियों के साथ चर्चा समूह, पारिवारिक संपर्क, इंटर्नशिप कार्यक्रम या विद्यालय के कार्यकर्ताओ द्वारा परामर्श जैसी तकनीकों का उपयोग करके रवैया, मूल्यों या निजी परिस्थितियों से सम्बन्धित हैं, जो सीखने के रास्ते में आ रहे हैं।

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 9 Issue 5, May 2019,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

- संरचनात्मक कार्यक्रम उन नीतियों को बदलते हैं, जो छात्रो की विद्यालय में उपस्थिति, प्रगति या पूरा करने, नीतियाँ जारी करने में बाधा डालते है, जैसे कि विद्यालय के लचीले कार्यक्रम ताकि विद्यालय की दूरी या उपज के मौसम से सामंजस्य बैठाया जा सके, स्वतः अगली कक्षा में जाना, के लिए प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा (अनुदेश) के लिए मातृ भाषा या माता–पिता– अध्यापक समूहों को विद्यालय की उपस्थिति या गुणवत्ता को जाँचने के लिए तैयार करना।

3. ड्रॉपआउट रोकने के लिए सरकारी प्रयास

भारतीय संविधान का अनुच्छेद–21 शिक्षा का अधिकार देता है, जिसके तहत 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है। इसके अलावा राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत में भी अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है।

इसलिए देश के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा देना राज्य का कर्तव्य भी है और बाध्यता भी। सरकार ने समय–समय पर विभिन्न योजनाएं चलाई हैं, जिनमें सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील, एकलव्य विद्यालय, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय आदि प्रयास किये जा रहे हैं।

- **कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय**

बच्चियों में सबसे ज्यादा ड्रॉपआउट रेट देखा गया है, क्योंकि शौचालय से लेकर यातायात और सुरक्षा का मसला सबसे ज्यादा उन्हीं के साथ होता है। सरकार ने इससे निपटने और अच्छी शिक्षा देने के लिए इन आवासीय विद्यालयों का निर्माण करवाया ताकि एक बेहतर वातावरण में उनकी शिक्षा–दीक्षा हो सके। हालांकि अभी भी इन योजनाओं में कई समस्या से निपटना बाकी है।

- **मिड–डे–मिल की योजना**

प्रायः यह देखा गया था कि बच्चे दोपहर को खाना खाने घर जाते थे और फिर वापस स्कूल नहीं आते थे। वे अक्सर घर के कामों में लग जाते थे। इससे स्कूलों में उपस्थिति भी प्रभावित होती थी और पढ़ाई भी।

इस समस्या से निपटने के लिए ही सरकार ने मिड–डे–मील योजना की शुरुआत की जिसके तहत बच्चों को दोपहर में स्कूल में ही पर्याप्त और पौष्टिक खाना देने की व्यवस्था की गई। इसके सकारात्मक परिणाम निकले और बच्चों की उपस्थिति बढ़ी।

हालांकि हाल के कुछ दिनों में मिड–डे–मील में छिपकली या सांप गिरने की घटना या फिर किसी और तरीके से विषाक्त भोजन परोसने की घटनाओं ने इसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किये हैं और इनसे निपटना जरूरी है।

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 9 Issue 5, May 2019,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

- **एकलव्य विद्यालय**

ड्रॉपआउट के आंकड़ों को देखें तो पता लगता है कि ज्यादातर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। कारणों की चर्चा भी हम कर चुके हैं। इस समस्या पर गंभीरता से सोचने के बाद एकलव्य विद्यालयों की स्थापना की गई।

- **समेकित शिक्षा योजना की शुरुआत की गई**

प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान के तहत साल 2015–16 के 15 लाख अतिरिक्त अध्यापक पद स्वीकृत किये गए हैं। उत्तराखण्ड में सपनों की उड़ान नाम का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य ड्रॉपआउट रेट में कमी लाना है।

- **ड्रॉपआउट के नकारात्मक प्रभाव**

ड्रॉपआउट की वजह से स्कूली शिक्षा पर काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। खासकर ग्रामीण इलाकों में बच्चों की शिक्षा पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इससे संसाधनों पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। मानव संसाधन तैयार करने के लक्ष्य को झटका लगता है।

एक बड़ी आबादी सरकार पर अतिरिक्त बोझ की तरह होती है, जिसकी जरूरतों का ध्यान सरकार को रखना पड़ता है और देश अन्य मुद्दों पर ध्यान नहीं दे पाता, इसलिए जरूरी है कि इन समस्यायो पर ध्यान दिया जाए और ठोस कदम उठाये जाएं। तभी इससे निजात मिलेगी और शिक्षित समाज और देश का निर्माण हो पाएगा।

4. ड्रॉपआउट बच्चों को स्कूल लाने की तैयारी

ड्रॉपआउट छात्रों को स्कूल जा रहे बच्चों के बराबरी पर लाने के लिए अब सर्व शिक्षा अभियान के तहत विशेष प्रशिक्षण केंद्र खोलने की तैयारी हो रही है। यह प्रशिक्षण सेंटर स्कूलों में या किसी स्वयंसेवी संगठन की निगरानी में होगा जो बच्चों के लिए सुरक्षित हो।

ड्रॉपआउट छात्रों को प्रशिक्षण केंद्र पर भेजने से पहले उन्हें रेग्यूलर स्कूलों में दाखिला कराया जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान योजना विभाग की ओर से इस संबंध में निर्देश भी जारी कर दिया गया है। दिल्ली में ड्रॉपआउट छात्रों के लिए अलग–अलग जिलों में कुल 17 प्रशिक्षण केंद्र खोले गए हैं।

इसे चलाने की जिम्मेदारी अलग–अलग स्वयंसेवी संस्थाओं को दी गई है। शिक्षा का अधिकार कानून के तहत बच्चों को तीन महीने से लेकर दो साल तक का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस दौरान उन्हें दूसरे बच्चों

जो कि रेग्यूलर स्कूल जा रहे है उनके बराबरी तक लाने के बाद दोबारा से उन्हें क्लासरूम में वापस भेजा जाएगा।

प्रशिक्षण शुरू करने से पहले छात्रों का रेग्यूलर स्कूलों में दाखिला दिया जाएगा। इसे लेकर दिल्ली सरकार के सभी स्कूलों के प्रमुखों व उपशिक्षा निदेशकों को निर्देश जारी कर दिया गया है। मालूम हो कि दिल्ली में हर साल हजारों की संख्या में छात्र किसी न किसी कारण से स्कूल छोड़ देते है। अब उन बच्चों को दोबारा से स्कूल तक लाने की योजना है। उम्र को ध्यान में रखते हुए उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर में दी जाएगी। उन्हें दोबारा स्कूल भेजा जाएगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची –

- विटारो, फ्रैंक, डेनिस लैरोक, मिशेल यैनोश, और रिचर्ड ई ट्रेम्ब्लेय। श्नकारात्मक सामाजिक अनुभव और स्कूल छोड़ना।श शैक्षिक मनोविज्ञान, वॉल्यूम 21, नंबर 4, 2001
- अडेयर, वी.सी. (2001) श्गरीबी और शिक्षा का (टूटा) वादा।श हार्वर्ड शैक्षिक समीक्षा, 71 (2), पीपी. 217–239.
- बॉनिया, काड़ा (2007) श्संक्षिप्त 3रू स्कूल छोड़ना क्या है?श स्कूल छोड़ने वालों की रोकथाम – हाई स्कूल स्नातक दरों में सुधार करने के लिए रणनीतियाँ। बाल एवं परिवार नीति केंद्र, ड्यूक विश्वविद्यालय. पीपी. 14–17
- (अगस्त 2010)। दक्षिणी घाना में स्कूल छोड़ने वालों की किस्म सृजित करें। सबातेस, आर.; एक्यिएमपोंग, के.; वेस्टब्रुक, जे. और हंट, एफ. (2010) स्कूल छोड़ने वालेरू नमूर्न, कारण, परिवर्तन और नीतियां। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन
- (अनंग, 2010) (सेबातेस, एक्यमपोंग, वेस्टब्रुक, और हंट, 2010)
- (यूनेस्को, 2015, पृ. 27) (सेबातेस, एक्यमपोंग, वेस्टब्रुक, और हंट, 2010) (लेविन और लिटिल, 2010)
- (रॉबर्ट बेलफॉज (एमए 2007). आपका समुदाय अपने स्कूल छोड़ने के संकट को समाप्त करने के लिए क्या कर सकता हैरू व्यवहारों के अनुसंधान से सीख। स्कूलों के सामाजिक संगठन का सीएसओएस केंद्र। जॉन्स हॉपकिन्स विश्वविद्यालय।
- रिकार्डो सबातेस, क्वामे एक्यमपोंग, जो वेस्टब्रुक और फ्रांसिस हंट। (2010). स्कूल छोड़ने वालेरू नमूर्न, कारण, परिवर्तन और नीतियां। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन ब्रश, लोरी, जेनिफर शिन, रजनी श्रेष्ठ, करेन तियत्येन। स्कूल छोड़ने वालों की रोकथाम का पायलटरू साहित्य की समीक्षा। क्रिएटिव एसोसिएट्स इंटरनेशनल। क्रिएटिव एसोसिएट्स इंटरनेशनल। वाशिंगटन डी सी। 2011

- लिम, एसए; रम्बर्गर, आर.डब्ल्यू. (2008)। छात्र स्कूल क्यों छोड़ते हैंरू 25 साल के अनुसंधान की एक समीक्षा। कैलिफोर्निया ड्रॉपआउट रिसर्च प्रोजेक्ट
- ब्रश, लोरी, जेनिफर शिन, रजनी श्रेष्ठ, करेन तियत्येन। स्कूल छोड़ने वालों की रोकथाम का पायलटरू साहित्य की समीक्षा। क्रिएटिव एसोसिएट्स इंटरनेशनल। क्रिएटिव एसोसिएट्स इंटरनेशनल। वाशिंगटन डी सी। 2011
- ब्रश, लोरी, जेनिफर शिन, रजनी श्रेश्ठ, करेन तियत्येन। स्कूल छोड़ने वालों की रोकथाम का पायलटरू साहित्य की समीक्षा। क्रिएटिव एसोसिएट्स इंटरनेशनल। क्रिएटिव एसोसिएट्स इंटरनेशनल। वाशिंगटन डी सी। 2011